पैकेज के बावजूद चीनी मिलों को कर्ज नहीं

अजीत सिंह

नई दिल्ली। केंद्र से राहत पैकेज मिलने के बावजूद चीनी मिलों को ब्याज मुक्त कर्ज नहीं मिल पा रहा है। चीनी उद्योग को वित्तीय संकट से उबारने और गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने 6,600 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त कर्ज का ऐलान किया था, लेकिन कर्ज देने के लिए बैंकों ने कड़ी शर्तें लगा दी हैं। इससे मिलों को कर्ज मिलना मुश्किल हो गया है।

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इसमा) के महानिदेशक अबिनाश वर्मा ने अमर उजाला को बताया कि चीनी मिलों का राहत पैकेज मंजूर हुए करीब दो महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी मिल को पैकेज के तहत कर्ज नहीं मिल पाया है। वर्मा ने बताया कि 10-12 जनवरी से चीनी मिलों ने कर्ज पाने के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया है, लेकिन बैंकों ने कर्ज देने के लिए कड़ी शर्तें लगा दी हैं। ऐसे में पिछले दो साल से चीनी मिलें जिस तरह का घाटा उठा रही हैं, उसे देखते हुए इन शर्तों पर कर्ज मिलना बेहद मुश्किल है।

किसानों का बकाया 10,000 करोड़ पहुंचा

जनवरी के आखिर तक देश भर में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान 10 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अकेले उत्तर प्रदेश में चालू पेराई सत्र का 14 दिनों से ज्यादा बकाया भुगतान 5 हजार करोड़ रुपये से ऊपर है, जबकि पिछले सीजन का करीब 1,300 करोड़ रुपये का भुगतान भी अटका हुआ है।

चीनी उत्पादन में 17% की गिरावट : देश का चीनी उत्पादन चालू चीनी सत्र के पहले चार महीने अक्तूबर-जनवरी के दौरान 17 फीसदी गिरकर 115.4 लाख टन पर आ गया। उत्पादन घटने की वजह गन्ना पेराई में देरी रही। 31 जनवरी 2014 तक भारतीय चीनी उद्योग ने 115.4 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है।

Amar Ujala
4/2/14